पुलिस की गश्तों के द्वारा और जो गलत प्रकार के लोग हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने के द्वारा और जिन-जिन एरियाज में अपराध ज्यादा हैं वहां पर पुलिस की हाई विजिबिलिटी हो इस माध्यम से और इम्प्रूव्ड इंटेलीजेंस के द्वारा जो कदम उठाए हैं उनका परिणाम आया है। लेकिन मैं मानूंगा कि और कदम उठाने की जरूरत है। आपने इस कांड का उल्लेख किया कि जिसमें कई लोग बीमार हो गए, फूड पाइजनिंग था या कुछ और था—इसकी छानबीन हो रही है।

श्रीमती वीणा वर्मा: सर, सेकेंड क्वेश्चन। खास तौर से महिलाओं के जो मामले हैं चाहे बलात्कार हो या उन पर कोई छीना-झपटी हो या उन पर कोई अत्याचार हो, मोलेस्टेशन हो तो उनमें यह देखा जाता है कि पहले तो एफ०आई०आर० नहीं लिखी जाती है। महिला थाने खोलने के लिए भी आपका सुझाव था। सोनीपत, हरियाणा में बहुत से महिला थाने खोले गए थे पिछले समय। मैंने चार वर्ष पूर्व उसको उठाया भी था। 18 महिला थाने खोले गए। उनको एक तो ब्यूरोक्रेट्स और कुछ कहिए कि प्रभावशाली लोगों और राजनीतिक, पुलिस ने मिलकर बंद करवाने की कोशिश की और वे बंद किए गए। उनमें काफी केसेज निपटाए गए थे, अच्छी तरह से जिम्मेदारी से निपटाए गए थे। तो क्या मंत्री जी पहले तो मुझे आश्वासन देंगे कि महिला थाने स्पेशली महिलाओं के द्वारा ही चलें जहां एफ०आई०आर० लिखवाई जा सके? क्या उस पर आप जोर देंगे? उनको खुलवाने के सिवाय दूसरी चीज जो एन०सी०डब्ल्यू०, जो महिला कमीशन है क्या उसको यह पावर देने की भी आप सोचेंगे कि वहां पर जो रिपोर्ट दर्ज की जाए वह एफ०आई०आर० समझी जाए?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महिला थानों का जो सुझाव है वह काफी समय से विचाराधीन रहा है। कई राज्यों में सफलतापूर्वक क्रियान्वित हुआ है। दिल्ली में कुछ साल पहले प्रयोग हुआ। वह सफल नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैंने अपने पुलिस अधिकारियों को कहा कि इस पर फिर से विचार करना चाहिए। उनका कहना यह है कि दिल्ली में सफल नहीं हुआ है ...**(व्यवधान)**

श्रीमती वीणा वर्मा: उसमें तो सफलता रही है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: लेकिन इस पर जरूर विचार करेंगे। कुल मिलाकर के भी यहां निर्णय हुआ है कि 17 और नये थाने खोले जाएं और वैसे साधारणतया बहुत समय लगता है लेकिन मैं आशा करता हूं कि 31 जनवरी, 1999 के महीने तक ये आपरेशनल हो जाएंगे।

MR. CHAIRMAN: Question No. 58, on the same subject. Shri K.K. Birla. Do you want to put a question? *(Interruptions)*.

श्रीमती वीणा वर्मा: महिला थाने और एन०सी०डब्ल्यू०ए०—नेशनल कमीशन फार वीमेन में जो एफ०आई०आर० लिखी जाए या जो एप्लीकेशन दर्ज हो वह एफ०आई०आर० मानी जाए इसके बारे मे बताएं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महिला आयोग के अपने अधिकार हैं और उनमें कोई बढ़ोत्तरी का कंक्रीट प्रस्ताव आएगा तो जरूर विचार करेंगे।

SHRIMATI JAYANTHI NATRAJAN: First, appoint a Chairman for the National Commission for Women.

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय: सभापति महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी से केवल यह कहना चाहूंगी कि जो आंकड़े आपने दिए है उन आंकड़ों में आपने कहा है।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Proposal to Construct A Hotel at Borra Caves

*45. SHRI SOLIPETA RAMA CHANDRA REDDY: Will the Minister of TOURISM be pleased to state:

(a) whether Borra caves near Araku valley in Vizag District in Andhra Pradesh are unique in our country;

(b) whether I.T.D.C. has any proposal to construct a hotel for the convenience of middle class tourists in that area;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF TOURISM (SHRI MADAL LAL KHURANA): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) I.T.D.C.'s Annual Plan 1998-99 does not include any proposal for the construction of a Hotel in the Vizag area. Accommodation for the convenience of middle class tourists are available in and around the area.

सेना में अधिकारियों के रिक्त पद

*46. **श्री डी०पी० यादव:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सेना में अधिकारियों के कुल कितने पद इस समय रिक्त हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सेना में अधिकारियों की कमी से सेना का मनोबल गिरा है; और

(ग) क्या सरकार ने अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने हेतु कोई कार्रवाई की है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडिस): (क) से (ग) इस समय सेना में 13,271 अफसरों की कमी है। तथापि, अफसरों की कमी होना कोई नई बात नहीं है। विगत में भी यह कमी अलग-अलग स्तरों पर रही है। अफसरों की कमी से सेना के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

सेना में अफसर संवर्ग में कमी पूरी किए जाने के लिए विभिन्न उपाय शुरू किए गए हैं, यथा विश्वविद्यालय प्रवेश योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर के "ग" प्रमाण-पत्र धारकों को अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अफसर के रूप में भर्ती किए जाने के लिए उन्हें सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा में बैठने से छूट देना, महिलाओं की अफसरों के रूप में भर्ती, सेवारत जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों/अन्य रैंकों को विशेष कमीशन प्राप्त अफसर संवर्ग में पदोन्नति देना और 10+2 तकनीकी प्रवेश योजना शुरू करना।

एक व्यावसायिक विज्ञापन एजेंसी की सहायता से 1997-98 के दौरान सेना की छवि-प्रदर्शन का अभियान चलाया गया था। इस दिशा में हुई उपलब्धियों को और समेकित करने के लिए सरकार ने इस अभियान का चरण-II शुरू करने का निर्णय लिया है।

सरकार ने सशस्त्र सेना कार्मिकों के लिए पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों में और सुधार करते हुए उन्हें लागू कर दिया है।

यह आशा है कि इन सभी प्रयासों के समवेत प्रभाव के फलस्वरूप भर्ती में वृद्धि होगी, जिससे निकट भविष्य में अफसरों की कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी।

Action Plan to fight insurgency in North-East

*47. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have since prepared an Action Plan to fight increasing insurgency in North-East region;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (c) Insurgency in the North East has never been looked upon only as a law and order problem. The development and deepening of democratic processes has been the basic framework within which the problems of the North-East have been approached. Development strategy since Independence has been pursued within the broad framework of planning with a view to ensure that people develop along the lines of their own genius and nothing should be imposed on them and that traditional way of life and culture are encouraged. The efforts should be to train and build indigenous teams to do the work of administration and development and that development should come through indigenous social and cultural institutions.

The strategy to curb insurgency includes a willingness to meet and discuss legitimate grievances; resolve that violence would not be tolerated; friendly relations with neighbouring countries; accelerated infrastructural development; stress on employment schemes; and good governance and decentralisation.

The State Governments have formulated their own Action Plans to fight insurgency. The Union Government monitors, cordinates and reinforces these Plans. The steps taken by the Central